नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 308
दि. 12.03.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

योगी कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों पर फैसला, शेयर मार्केट में निवेश और प्रॉपर्टी खरीद की देनी होगी जानकारी

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 30 प्रस्ताव पारित हुए। इस दौरान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में छह महीने के मूल वेतन से अधिक राशि स्टाक, शेयर मार्केट या अन्य निवेश में लगाने पर इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 में संशोधन होगा।

यूपी में कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब छह महीने के मूल वेतन की राशि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में लगाने पर उसकी सूचना प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी। इसके अलावा अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने दो महीने की सैलरी से ज्यादा वैल्यू की किसी भी चल संपत्ति (जैसे- गाड़ी, सोना) का लेनदेन करता है, तो उसे इसकी सूचना देनी होगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाएगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा।

पहले एक महीने का था नियम

गौरतलब है कि पहले एक महीने के मूल वेतन से अधिक की चल संपत्ति का विवरण देना होता था। अब हर साल अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा। कमचारियों को अपनी नियुक्ति के समय और उसके बाद हर साल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी देनी होगी। अभी यह घोषणा हर पांच साल में करने का नियम है।

दान में मिली संपत्ति के बारे में भी बताना होगा

यूपी सरकार अभी भी हर साल कर्मचारियों से संपत्ति का ब्योरा लेती है लेकिन अब नियमावली में बदलावा कर यह व्यवस्था और सख्त करने की तैयारी है।

नियमों के मुताबिक, राज्य कर्मचारियों को अपनी या परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित, दान में प्राप्त, पट्टे पर रखी संपत्तियों या अन्य निवेशों की जानकारी भी देनी जरूरी होगी।

रोका जा सकता है प्रमोशन

राज्य कर्मचारियों को सेवा नियमावली नियम 24 में किए गए बदलावों के तहत हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों का प्रमोशन रोका जा सकता है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

पीम मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तथा और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तमिलनाडु के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए ऐतिहासिक शहर त्रिची का दौरा किया। कुल 5,600 करोड़ रुपये के निवेश वाली इन पहलों में स्वच्छ ऊर्जा, पेट्रोलियम से संबंधित विनिर्माण और राजमार्गों, रेलवे और ग्रामीण सड़कों के माध्यम से बेहतर बहु-मार्गीय संपर्क सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'ये परियोजनाएं ऊर्जा की उपलब्धता और संपर्क को बढ़ावा देंगी तथा तमिलनाडु के युवाओं के लिए हजारों रोजगार सृजित करेंगी।'

प्रधानमंत्री ने सतत ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत पेट्रोलियम के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क की आधारशिला रखी। 3,700 करोड़ रुपये की यह परियोजना लगभग 9 लाख परिवारों और कई व्यावसायिक संस्थाओं को पाइप से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपलब्ध कराकर नीलगिरी और इरोड जिलों को बदलने के लिए तैयार है। श्री मोदी ने पर्यावरणीय लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'केवल आठ वर्षों में इस परियोजना का सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव चार करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि चेन्नई में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लुब्रिकेंट ब्लेंडिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करना 'मेक इन इंडिया' पहल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि विश्व स्तर पर अपनी तरह की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक यह प्लांट राज्य के भीतर और बाहर के विभिन्न उद्योगों की उच्च मांगों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। श्री मोदी ने कहा, "लुब्रिकेंट के स्थानीय उत्पादन में वृद्धि से आयात में कमी आएगी और देश के धन की बचत होगी।"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित 370 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करके ग्रामीण संपर्क के महत्व पर जोर दिया। इन सड़कों से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलने की संभावना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यधारा से जुड़ सकेगी।

इस विकास पर प्रधानमंत्री ने कहा, 'प्रत्येक सड़क ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है और जीवन स्तर को सुगम बनाती है।'

प्रधानमंत्री ने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए, गंगईकोंडा चोलपुरम में एक नए राजमार्ग बाईपास परियोजना की घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य यूनेस्को से मान्यता प्राप्त सम्राट राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित भव्य मंदिर की रक्षा करना है, जिसके लिए भारी यातायात को पवित्र स्थल से दूर मोड़ा जाएगा, जिससे स्मारक और उसके आगंतुकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नए बुनियादी ढांचे के बारे में श्री मोदी ने कहा, 'इसका मतलब है सभी के लिए बेहतर सुरक्षा।'

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के समापन में अमृत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आठ स्टेशनों के हालिया आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के बाद राज्य के परिवहन क्षेत्र के तीव्र आधुनिकीकरण का उल्लेख किया। आज शुरू की गई नई रेल सेवाएं नागरकोइल, कोयंबटूर, रामेश्वरम, तिरुनेलवेली, मयिलादुथुराई, कराईकुडी जैसे प्रमुख स्थानों को अन्य क्षेत्रों से जोड़ती हैं, जिससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने राज्य के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा, 'हम राज्य की प्रगति के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से से मिले नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव, लोहम कंपनी के सीईओ से भी मुलाकात

लखनऊ। (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव व लोहम कंपनी के सीईओ रजत वर्मा और कंपनी के चीफ ऑफ स्टॉफ आयुष सबात ने मुलाकात की। इस दौरान एडवांस्ड मटेरियल रिसर्च और इंजीनियरिंग का प्रमुख हब बनाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने बुधवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान लोहम कंपनी के सीईओ रजत वर्मा और कंपनी के चीफ ऑफ स्टॉफ आयुष सबात भी मौजूद रहे। तीनों अतिथियों ने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश के सकारात्मक माहौल की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव, लोहम के सीईओ रजत वर्मा और चीफ ऑफ स्टाफ आयुष सबात का उत्तर प्रदेश में स्वागत किया।

बैठक में उत्तर प्रदेश को देश में एडवांस्ड मटेरियल रिसर्च और इंजीनियरिंग का प्रमुख हब बनाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस क्रम में लोहम द्वारा प्रदेश में भारत की पहली 'रेयर अर्थ टू मैग्नेट' इंटीग्रेटेड फैसिलिटी स्थापित करने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस फैसिलिटी के स्थापित होने से देश में उच्च तकनीक आधारित मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

नोबेल पुरस्कार विजेता कोंस्टेंटिन नोवोसेलोव, जो ग्रैफीन की खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, लोहम कंपनी के साथ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर और सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य उन्नत मटेरियल साइंस को औद्योगिक स्तर पर बैटरी तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में लागू करना है।

लोहम और नोवोसेलोव के सहयोग का मुख्य फोकस दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर है। पहला, 2ऊ मटेरियल (जैसे ग्रैफीन) का उपयोग कर अगली पीढ़ी की लिथियम-आयन बैटरियों की क्षमता, सुरक्षा व लाइफ को बढ़ाना। दूसरा, बैटरियों और परमानेंट मैग्नेट का उन्नत रीसाइक्लिंग सिस्टम विकसित कर महत्वपूर्ण खनिजों की बेहतर रिकवरी सुनिश्चित करना, जिससे सर्कुलर इकॉनमी को मजबूती मिलेगी। यह सहयोग भारत के 'मेक इन इंडिया' और ग्रीन एनर्जी विजन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

'जब बोलना होता है तो विदेश में होते हैं', अमित शाह ने सदन में पढ़ा राहुल गांधी का अटेंडेंस चार्ट

(जीएनएस)।

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण एक नाटकीय बहस का गवाह बना, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने सदन का माहौल गरमा दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी जुबानी जंग हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला।

सदन में बोलने नहीं दिया जाता

राहुल गांधी के दावे पर अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सदस्य खुद तय करते हैं कि उन्हें बहस में कब शामिल होना है। शाह ने आरोप लगाया कि जब सदन में बोलने के अवसर मिलते हैं, तो गांधी अक्सर विदेश जैसे जर्मनी और इंग्लैंड में होते हैं।

अमित शाह ने सदन में पढ़ा राहुल गांधी का अटेंडेंस चार्ट

केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता की लोकसभा में उपस्थिति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि की 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति 51 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 66 प्रतिशत रहा। इसी तरह 16वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 52 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 80 प्रतिशत था। 15वीं लोकसभा में भी उनकी उपस्थिति 43 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 76 प्रतिशत रहा था।

लोकसभा में बोलने के समय पर उठाए सवाल

गृह मंत्री ने सदन को बताया कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने कुल 157 घंटे 55 मिनट तक बात की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि विपक्ष के नेता ने इनमें से कितना समय बोला। शाह ने कहा, "कौन से स्पीकर ने गांधी को बोलने से रोका है और ऐसा कोई नहीं कर सकता", उन्होंने दावा किया कि लोकसभा को बदनाम करने के लिए गलत जानकारी फैलाई जा रही है।

अमित शाह ने नेहरू और इंदिरा गांधी का किया जिक्र

गृह मंत्री ने राहुल गांधी द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सदन में बहस की मांग की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोकसभा कोई बाजार नहीं है जहां इस तरह की चर्चाएं आयोजित की जा सकें। उन्होंने कहा, "लोकसभा कोई बाजार नहीं है जहां ऐसी चर्चाएं आयोजित की जा सकें।" शाह ने याद दिलाया कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रमुख नेताओं के समय में भी किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सदन में कभी बहस नहीं हुई थी।

अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस "झूठे दावों" पर आधारित थी।

स्पीकर ओम बिरला का बचाव

उन्होंने डे Birla का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने सदन के मानकों को गिरने नहीं दिया बल्कि उसकी गरिमा बनाए रखी। शाह ने कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस की अनुमति न देकर ओम बिरला ने सदन पर एक एहसान किया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भड़के अनुराग ठाकुर, 'विपक्ष बस आरोप लगा रहा, कोई तथ्य नहीं दिए'

(जीएनएस)।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संसद की सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस तर्क, तथ्य या आधार पेश करने में पूरी तरह विफल रहा है।

मीडिया से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का राजनीतिक कदम है, लेकिन इसके पीछे कोई मजबूत कारण नजर नहीं आता। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में गंभीर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है।

अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, 'लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। अब तक की चर्चा में विपक्ष अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस तर्क, तथ्य या आधार पेश नहीं कर पाया है। इसके बजाय सदन में उनका आचरण ही अनुचित रहा है।' उन्होंने आगे कहा कि संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और यहां सभी जनप्रतिनिधियों से गरिमापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। ठाकुर के मुताबिक विपक्ष का हालिया व्यवहार न केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अनुचित है, बल्कि यह संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का भी उल्लंघन करता है।

OM Birla के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कैसे आता है, क्या है पूरा नियम?

दरअसल, विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कामकाज और सदन के संचालन को लेकर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष का आरोप है कि सदन की कार्यवाही के दौरान उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा और सरकार के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। हालांकि, बीजेपी और एनडीए के अन्य सहयोगी दलों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि स्पीकर ने हमेशा संसदीय नियमों और परंपराओं के अनुसार ही सदन का संचालन किया है।

इस मुद्दे को लेकर संसद में आने वाले दिनों में और राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है। पीठासीन अधिकारी ने इस पर बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया है। यह विवाद संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव को भी दर्शाता है। फिलहाल लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों पक्ष अपने-अपने तर्कों के साथ सामने आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को जारी करेंगे पीएम-किसान की 22वीं किस्त; केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी

देश भर के 9.32 करोड़ किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रु. से अधिक राशि होगी जमा- श्री शिवराज सिंह

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसानों के खाते में सीधी मदद, 22वीं किस्त के साथ ही कुल हस्तांतरित राशि 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी- श्री शिवराज सिंह

महिला किसानों और छोटे जोतधारकों के लिए मजबूत सहारा बनी पीएम-किसान योजना, 22वीं किस्त में 2.15 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थी- श्री शिवराज सिंह चौहान

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2026 को गुवाहाटी (असम) से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यह जानकारी देते हुए इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के प्रति केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता और 'अन्नदाता सम्मान' की संकल्पबद्ध पहल बताया।

22वीं किस्त के साथ ही कुल हस्तांतरित राशि 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फरवरी 2019 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक पीएम-किसान के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों के खातों में 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे भेजी जा चुकी है और 22वीं किस्त जारी होने के साथ ही कुल हस्तांतरित राशि 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आय समर्थन देकर कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और स्थायी परिवर्तन की नींव रखी है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बताया कि पीएम-किसान योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को साल में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है और यह राशि पूरी तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे पहुंचती है।

22वीं किस्त में 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समय पर मिलने वाली यह सहायता किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसी कृषि सामग्री खरीदने में मदद करती है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक घरेलू जरूरतों को पूरा करने में भी सहारा देती है।

श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों, विशेषकर महिला किसानों को सशक्त बनाने की दृष्टि को रेखांकित करते हुए कहा कि केवल 22वीं किस्त में ही 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी जिससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और गांवों में महिला सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी।

पीएम-किसान योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र अध्ययनों ने भी प्रमाणित किया है कि पीएम-किसान योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाई है। किसानों की कर्ज पर निर्भरता कम की है और कृषि निवेश को प्रोत्साहित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने स्पष्ट किया कि पीएम-किसान पूरी तरह प्रौद्योगिकी आधारित और पारदर्शी योजना है जो भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से संचालित होती है और इसमें किसी प्रकार के बिचौलियों की कोई गुंजाइश नहीं है।

नवसर्जन संस्कृति हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

केडी सिंह बाबू स्टेडियम के हैंडबॉल ट्रेनीज ने जीते दोहरे खिताब

जिला स्तरीय जूनियर बालक-बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता

लखनऊ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम की टीम ने खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और क्षेत्रीय खेल कार्यालय, लखनऊ के तत्वावधान में लखनऊ जिला हैंडबॉल एसोसिएशन के सौजन्य से आयोजित जिला स्तरीय जूनियर बालक-बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन से दोनों वर्गो की विजेता ट्रॉफी जीत ली।

केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्थित भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी बहुउद्देश्यीय हाल में आयोजित प्रतियोगिता में बालिका वर्ग के

फाइनल में केडी सिंह बाबू स्टेडियम ने चौक स्टेडियम की टीम को रोमांचक मुकाबले में 15-12 से हराया। दूसरी ओर बालक वर्ग के फाइनल में भी केडी सिंह बाबू स्टेडियम की टीम विजेता बनी जिसने चौक स्टेडियम ट्रेनीज को 25-23 से शिकस्त दी।

प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपक्रीड़ाधिकारी राजेश कुमार गौड़ ने किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का स्वागत केडी सिंह बाबू स्टेडियम के हैंडबॉल कोच मो तौहीद ने किया।

वहीं समापन समारोह में लखनऊ जिला हैंडबॉल एसोसिएशन के सचिव डा सुमंत पाण्डेय ने पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर चौक स्टेडियम की हैंडबॉल कोच अंकिता रत्न व अन्य मौजूद रहे। एक दिवसीय इस प्रतियोगिता मे बालक व बालिका दोनो ही वर्गो में आठ-आठ टीमों ने भाग लिया था जिनके मध्य नाकआउट मुकाबले खेले गए थे।

कैस्ट्रोल 'सारथी मित्र' कार्यक्रम के तहत चालकों को दिया जा रहा सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण

ट्रांसपोर्ट नगर में आयोजित शिविर में करीब 1000 ड्राइवरों ने लिया प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा और सुरक्षित ड्राइविंग की दी गई जानकारी

लखनऊ। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैस्ट्रोल के 'सारथी मित्र' कार्यक्रम के तहत चालकों को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों के पालन और दुर्घटनाओं से बचाव के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरूआत भारतीय सेना से सेवानिवृत्त प्रशिक्षक राजेंद्र सिंह द्वारा की गई, जिनके माध्यम से ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग, वाहन रख-रखाव और आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले उपायों की जानकारी दी जा रही है।

लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में लगभग 1000 चालकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान चालकों को रिफ्लेक्टर स्टिकर, टी-शर्ट, कॉपी, सुरक्षा किट, जैन कार्ड के साथ निःशुल्क रिफ्रेशमेंट और भोजन भी उपलब्ध कराया गया।

परियोजना समन्वयक हर्षित शुक्ला के सहयोग से यह योजना उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में संचालित की जा रही है। यह पहल मुख्य रूप से ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों

के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी समस्याओं की जानकारी देकर समाधान प्राप्त कर सकें।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी कमलेश कुमार विभूति, एआरटीओ आलोक कुमार बाला, सीओ अभिषेक सिंह, एस.आई वीर भान सिंह, आर.के. सवर्ची, अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव तथा विज्ञापन प्रतिनिधि अपूर्व गुप्ता उपस्थित रहे।

कैस्ट्रोल 'सारथी मित्र' कार्यक्रम की ओर से सीएसआर हेड सुश्री रेखा पिल्लई, सीएफओ सुश्री मृणालिनी, प्रोजेक्ट हेड श्रीकांत कुलकर्णी, जोनल हेड विपिन आनन्द, फैसिलिटेटर रोहित शुक्ला, ट्रेनर राजेन्द्र सिंह तथा एकेडमिक हेड शिवांगी अस्थाना भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

आशुतोष पाठक ने ड्राइवरों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अंधे मोड़, संकरी पुल, रेलवे क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर और तिराहों जैसे दुर्घटना संभावित स्थानों के बारे में जानकारी देते हुए चालकों से सतर्कता के साथ वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से ड्राइवरों को दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय भी समझाए।

आरटीओ प्रभाकर पांडेय ने ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने, गति नियंत्रण रखने और सतर्कता के साथ वाहन चलाने की सलाह दी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

परियोजना समन्वयक हर्षित शुक्ला ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही महिलाओं और युवाओं को भी प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

हजरत अली (अ0) का न्याय आज भी इंसानियत के लिए मिसाल : मौलाना अली अब्बास खान

लखनऊ 'ऐनुल हयात ट्रस्ट' की ओर से इमाम हजरत अली (अ0) की शहादत के गम में 20 रमजान को छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद में रात 8:15 बजे एक मजलिस का आयोजन किया गया। मजलिस को मौलाना अली अब्बास खान साहब ने खिताब किया।

कार्यक्रम की शुरूआत कश्मीर के मशहूर कारी बशारत हुसैन साहब ने तिलावत-ए-कुरआन से की। उनकी तिलावत ने सभी लोगों को बहुत प्रभावित किया। इसके बाद मौलाना अली हादी साहब ने इमाम हजरत अली (अ0) का वसीयतनामा पढ़ा और कहा कि हमें उसकी बातों पर अमल करना चाहिए। वसीयतनामे की छपी हुई कॉपियां भी वहां मौजूद लोगों को दी गईं।

अपने बयान में मौलाना अली अब्बास खान साहब ने कहा कि दुनिया का हर इंसान इंसाफ चाहता है और कोई भी जुल्म पसंद नहीं करता। लेकिन लोग इंसाफ को सही तरह से नहीं समझते। हर कोई अपनी सोच के हिसाब से इंसाफ की परिभाषा कर लेता है।

उन्होंने कहा कि इमाम हजरत अली (अ0) ने बताया कि इंसाफ का मतलब है—हर चीज और हर व्यक्ति को उसका सही हक और सही जगह देना। अगर किसी को उसके हक से ज्यादा या कम दिया जाए तो वह ज़ुल्म है। सबको बराबर देना इंसाफ नहीं है, बल्कि जिसकी जितनी काबिलियत है, उसे उसी के हिसाब से ज़िम्मेदारी और बदला (इनाम या सजा) मिलना ही असली इंसाफ है।

मौलाना ने यह भी बताया कि अल्लाह ने दुनिया में हर चीज को अलग बनाया है—आंख का काम अलग है, हाथ का अलग, दिमाग का अलग। इसी तरह हर इंसान का काम अलग है। जब हर कोई अपना काम सही तरीके से करता है, तभी समाज में इंसाफ कायम होता है।

हजरत अली (अ0) की रहमत और अनाथों से मोहब्बत का ज़िक्र करते हुए मौलाना ने कहा कि रमजान की 20 तारीख की सुबह कूफा के अनाथ बच्चों को पता चला कि जो शख्स हर रात चुपके से उनके घर आकर मदद करता था, वह हजरत अली (अ0) ही थे।

मजलिस के आखिर में लोगों ने नम आंखों से हजरत अली (अ0) के उत्तराधिकारी इमाम मेहदी (अ0) की खिदमत में पुरसा पेश किया और हजरत अली (अ0) को श्रद्धांजलि दी।

संक्रमण नियंत्रण के लिए नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एसएस मेडिकल सिस्टम्स ने समझौते पर हस्ताक्षर किए

लखनऊ, । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एसएस मेडिकल सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण साझेदारी की।

इस समझौते पर औपचारिक रूप से कमोडोर अमित रस्तोगी (सेवानिवृत्त), प्रबंध निदेशक और डॉ. मोनीश भंडारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसएस मेडिकल सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड ने नागरूर लक्ष्मीनारायण, तकनीकी निदेशक और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

हरित चिकित्सा प्रौद्योगिकी में एक बड़ी सफलता इस साझेदारी के मूल में एसएस मेडिकल के इनोवेटिव माइक्रोवेव-आधारित मोबाइल संक्रमण नियंत्रण सिस्टम को बढ़ावा देना है। यह तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान, सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का परिणाम है।

इस सहयोग पर बात करते हुए, एनआरडीसी के सीएमडी, कमोडोर अमित रस्तोगी ने कहा की एनआरडीसी अस्पतालों, क्लीनिकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संक्रामक बायोमेडिकल कचरे के स्टरलाइजेशन हेतु एसएस मेडिकल के पेटेंटेड और पर्यावरण के अनुकूल समाधान का व्यवसायीकरण करने के लिए अपने अखिल भारतीय नेटवर्क का लाभ उठाएगा। एसएस मेडिकल सिस्टम्स के साथ इस साझेदारी के माध्यम से, एनआरडीसी का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में उन्नत संक्रमण नियंत्रण समाधानों की तैनाती में तेजी लाना और एक सुरक्षित तथा अधिक मजबूत स्वास्थ्य सेवा ढांचा बनाने के भारत के प्रयासों का समर्थन करना है।

इस अवसर पर एसएस मेडिकल सिस्टम्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. मोनीश भंडारी ने कहा कि एसएस मेडिकल में हमारे मूल सिद्धांत हमेशा नवाचार के माध्यम से भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के साथ जुड़े रहे हैं। यह साझेदारी हमें अपनी अत्याधुनिक, माइक्रोवेव-आधारित तकनीकों को देश के हर कोने तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। कचरा निपटान के पुराने तरीकों को हमारे टिकाऊ, 'मेक इन इंडिया समाधानों से बदलकर, हम सिर्फ कचरे का प्रबंधन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अस्पताल से होने वाले संक्रमण के बोझ को कम करके और रोगियों व स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करके सक्रिय रूप से जीवन बचा रहे हैं।

भारत में विदेशी एयरलाइंस पर नई पाबंदी! डीजीसीए की अनुमति के बिना अब नहीं होगी लैंडिंग

(जीएनएस)।

भारत के नागरिक उड्डयन नियामक निदेशालय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने देश में संचालन करने वाली विदेशी एयरलाइंस के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं। नए निर्देश के मुताबिक अब कोई भी विदेशी एयरलाइन उ्ख्नउअ की औपचारिक अनुमति के बिना भारत में

लैंडिंग नहीं कर सकेगी।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सरकार और विमानन नियामक एयरलाइन संचालन, सुरक्षा और नियमों के पालन पर कड़ी निगरानी बढ़ा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे भारतीय विमानन क्षेत्र में सुरक्षा, विश्वसनीयता और नियामकीय अनुपालन को और मजबूत किया जा सकेगा।

यूपी डब्ल्यूजेयू ने की पी एफ की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग

श्रम मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर वकालत का दिया आश्वासन

लखनऊ : 11 मार्च । उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह शीघ्र ही केंद्रीय श्रम मंत्री से भेंट कर पत्रकारों सहित निजी क्षेत्र के सभी अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को भविष्य निधि संगठन (पीएफ) से मिल रही मासिक ₹1000 न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹5000 करने की मांग पर बल देंगे ।

यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय श्रम मंत्री को संबोधित संबंधित ज्ञापन श्री अनिल राजभर को दिया । यह प्रस्ताव यूनियन के अयोध्या में आयोजित प्रादेशिक सम्मेलन में पारित किया गया था ।

प्रतिनिधि मंडल में यूनियन के प्रादेशिक महामंत्री देवराज सिंह लखनऊ इकाई के अध्यक्ष शिवशरण सिंह , अब्दुल हसनैन ताहिर , अशीष कुमार सिंह शामिल थे ।

यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ने बताया ₹1000 न्यूनातम पेंशन का निर्धारण करीब डेढ़ दशक पूर्व हुआ था । विभिन्न राज्य सरकारें महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों को हजारों रुपए पेंशन दे रही है , दूसरी ओर जीवन के कई दशक पूर्णकालिक नौकरी में गुजार देने वाले कर्मचारियों को केवल ₹1000 पेंशन दिया जाना हास्यापद एवं अन्याय पूर्ण है ।

श्री राजभर ने अश्वासन दिया की वह शीघ्र ही केंद्रिय श्रम मंत्री से भेंट कर यूनियन की मांग न केवल उन तक पहुंचाएंगे बल्कि मांग पूरी करने पर बल भी देगे ।

लडकी के साथ दुष्कर्म करने वाला वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बर्रा कमिश्नरेट कानपुर

कानपुरनगर। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल कमिश्नरेट कानपुर द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) कमिश्नरेट कानपुर नगर, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) कमिश्नरेट कानपुर नगर एंव सहायक पुलिस आयुक्त नौबस्ता कानपुर नगर के निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र नाथ श्रीवास्तव थाना बर्रा कानपुर नगर के नेतृव में बर्रा पुलिस की टीम द्वारा थाना बर्रा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2026 धारा 123/64(2)/308(2)/191(2)/352/351(2)/351(3)/140() बीएनएस थाना बर्रा कानपुर में त्वरित कार्यवाही करते हुये 24 घण्टे के अन्दर दुष्कर्म करने वाला नामजद अभियुक्त अथर्व सिंह पुत्र अमित सिंह निवासी म0 नं0 219 न्यू श्याम नगर नौबस्ता थाना हनुमंत

विहार जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 21 वर्ष को श्याम नगर नौबस्ता कानपुर नगर से गिरफ्तार किया गया। अन्य विवेचनात्मक विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त अथर्व सिंह उपरोक्त को न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त अथर्व सिंह पुत्र अमित सिंह निवासी म0नं0 219 न्यू श्याम नगर नौबस्ता थाना हनुमंत विहार जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 21 वर्ष का है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

इस प्रकार है मु0 अ0 सं0 80/2026 धारा123/64(2)/308(2)/191(2)/ 352/351(2)/351(3)/140(3)बीएनएस थाना बर्रा कानपुर नगर, गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव थाना बर्रा कमिश्नरेट कानपुर नगर ।

व0उ0नि0 श्री नन्दू सिंह थाना बर्रा कमिश्नरेट कानपुर नगर। हे0 का0 424 दारा सिंह थाना बर्रा कमिश्नरेट कानपुर नगर। म0का0 1267 किसमिसा सिंह थाना बर्रा कमिश्नरेट कानपुर नगर ।

तेजी से बढ़ रहा सवर्ण आर्मी संगठन, सदस्यता अभियान जारी

(जीएनएस)।

सोनभद्र। सवर्ण समाज के अधिकारों की आवाज उठाने के उद्देश्य से गठित सवर्ण आर्मी संगठन का विस्तार सोनभद्र जिले में लगातार तेजी से हो रहा है। संगठन के पदाधिकारी जगह-जगह जाकर लोगों को संगठन की विचारधारा से जोड़ने और सदस्यता अभियान चलाने में जुटे हुए हैं।

संगठन के कार्यकताओं का कहना है कि सवर्ण आर्मी का गठन उन कानूनों और नीतियों के विरोध में किया गया है, जिन्हें वे समाज में विभाजन पैदा करने वाला या किसी एक वर्ग को दबाने वाला मानते हैं।

संगठन का दावा है कि वह ऐसे कथित 'काले कानूनों' के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने के लिए लोगों को एकजुट कर रहा है।

सोनभद्र जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए कई पदाधिकारी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इसमें बिना नगर सचिव अमित दुबे, जिला सचिव सोनभद्र अनिमेष कुमार चौबे, जिला उपाध्यक्ष श्री विंध्यवासिनी सिंह तथा नगर सचिव शक्तिनगर पंकज चौबे प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये सभी पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, सवर्ण आर्मी समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर उनकी समस्याओं को उठाने और अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने का कार्य कर रही है। उनका कहना है कि आने वाले समय में संगठन का विस्तार और भी तेजी से किया जाएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा।

'राजपाल कम पढ़े लिखे', प्रियदर्शन के इस बयान से भड़के थे एक्टर, अब डायरेक्टर ने दी सफाई

(जीएनएस)।

फरवरी महीने में बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav एक पुराने चेक बाउंस मामले के कारण चर्चा में रहे। उन्होंने इस मामले में Tihar Jail में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद अदालत से उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिल गई। इसी दौरान एक पारिवारिक शादी में शामिल होने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ।

बाद में मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजपाल यादव ने पूरे मामले पर अपनी बात रखी और कहा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों का समर्थन और सहयोग मिलने के लिए आभार भी जताया।

प्रियदर्शन के बयान से बढ़ा विवाद

इसी बीच निर्देशक Priya darshan के एक पुराने बयान ने विवाद को हवा दे दी। दरअसल, जब राजपाल जेल में थे, तब प्रियदर्शन ने उनके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे "कम पढ़े-लिखे" हैं और शायद इसी वजह से उनसे ऐसी गलती हुई। यह बात सामने आने के बाद राजपाल यादव ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रियदर्शन उन्हें ठीक से जानते तक नहीं हैं और वे खुद को पढ़ा-लिखा व्यक्ति मानते हैं।

पुराने रिश्ते और साथ काम करने की कहानी

प्रियदर्शन के अनुसार उन्होंने राजपाल यादव को पहली बार 2000 में आई फिल्म Jungle में देखा था और तब से वे उन्हें करीब दो दशकों से जानते हैं। दोनों ने साथ में पहली बार फिल्म malamaal Weekly में काम किया था।

निर्देशक ने बताया कि एक समय राजपाल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपनी अगली फिल्म के निमार्ताओं से अभिनेता को तय रकम से अधिक फीस देने की सिफारिश भी की थी। मौजूदा समय में राजपाल उनकी एक फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं।

बयान पर दी सफाई

हाल ही में एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत में प्रियदर्शन ने इस पूरे विवाद पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान का अर्थ गलत समझ लिया गया। उनके मुताबिक वे राजपाल की शिक्षा नहीं, बल्कि उनकी मासूमियत और इंडस्ट्री में संघर्ष की परिस्थितियों की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी मिलती है। उनका आशय "स्ट्रीट स्मार्टनेस" से था, यानी परिस्थितियों को समझने की व्यावहारिक समझ से।

राजपाल की सादगी का किया ज़िक्र

प्रियदर्शन ने आगे कहा कि राजपाल का स्वभाव बेहद सरल और भरोसेमंद है। उनके मुताबिक गाँवों से आने वाले कई लोग इतने सीधे होते हैं कि उन्हें कई बार सही-गलत का अंदाजा देर से होता है। निर्देशक ने अंत में दोहराया कि उनका उद्देश्य राजपाल यादव का अपमान करना नहीं था। उन्होंने कहा कि अपने लंबे करियर में उन्होंने राजपाल जैसा निष्कपट इंसान बहुत कम देखा है और उनकी यही मासूमियत उन्हें खास बनाती है।

राज्य महिला आयोग अध्यक्ष 13 मार्च को सर्किट हाउस सभागार में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरणों की करेंगी जन सुनवाई

(जीएनएस)।

सोनभद्र/उत्तर प्रदेश। अपर जिलाधिकारी प्रोटोकाल ने अवगत कराया है कि राज्य महिला आयोग अध्यक्ष (राज्य मंत्री स्तर प्राप्त) डॉ0 बबिता सिंह चैहान का जनपद में सर्किट हाउस चुर्क में 12 मार्च को रात्रि में आगमन होगा, अध्यक्ष 13 मार्च 2026 को जिला महिला चिकित्सालय में कन्या जन्मवोत्सव कार्यक्रम में प्रातः 09:30 बजे प्रतिभाग करेगी, इसके पश्चात सर्किट हाउस में

जनपद में महिलाओं की उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरणों की जन सुनवाई करेंगीं, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इसके पश्चात सर्किट हाउस सभागार में महिलाओं का सम्मान गोद भराई व अन्नप्रासन कार्यक्रम में प्रतिभग करेगी इसके पश्चात वैष्णों माता मंन्दिर डाला में अध्यक्ष दर्शन व पूजन करेगीं इसके पश्चात जिला करागार महिला बन्दीगृह का निरीक्षण करेगी तद्द पश्चात अपने गनतब्य को प्रस्थान करेगी।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

ईरान के सर्वोच्च नेता चुन लिए गये मोजतबा हुए घायल

ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं। दुनिया के स्वयंभू बादशाह सलामत डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा यह मैं चुनूंगा। ईरान ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है और साफ बता दिया है कि ईरान ट्रंप-नेतन्याहू के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 88 सदस्यीय धार्मिक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर को चुनने की है। संस्था द्वारा जारी एक बयान को ईरानी टीवी पर एंकर ने पढ़कर सुनाया। बयान में कहा गया कि युद्ध में बेहद गंभीर हालात और हमारी संस्था के खिलाफ दुश्मनों की सीधी धमकियों के बावजूद और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सचिवालय के दफ्तरों पर बमबारी से उसके कई कर्मचारियों और सुरक्षा टीम के सदस्यों के शहीद हो जाने के बावजूद ईरानी व्यवस्था के नेतृत्व के चयन और उसकी घोषणा की प्राक्रिया एक पल के लिए भी नहीं रूकी। इसके बाद एंकर ने नारा लगाया-अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर खामेनेई ही रहबर। अमेरिकी-इजरायल के हवाई हमलों में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद कई लोगों को आशंका थी कि उनके बेटे मोजतबा खामेनेई भी मारे गए हैं। कई दिनों तक मोजतबा के बारे में कोई खबर नहीं आई। लेकिन तीन मार्च को ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि मोजतबा जिदा हैं और उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है। बता दें कि मोजतबा खामेनेई ने तो कभी कोई सार्वजनिक भाषण दिया ही नहीं, न कोई सरकारी पद संभाला, न कोई साक्षात्कार दिया और उनकी बहुत कम तस्वीरें और वीडियो प्राकाशित हुए हैं।

अमेरिकी राजनयिक दस्तावेजों में उन्हें पर्दे के पीछे असली ताकत बताया गया था। उनको शासन के भीतर एक सक्षम और दृढ़ नेता माना जाता है। 8 सितम्बर 1969 को ईरान के उत्तर पूवा शहर माशहद में जन्मे मोजतबा इमाम अली खामेनेई के 6 बच्चों में दूसरे स्थान पर हैं।

मीडिया के मुताबिक 17 साल की उम्र में मोजतबा ने ईरान-इराक युद्ध के दौरान सेना में सेवा दी थी। मदरसों की व्यवस्था में अयातुल्लाह के पदवी का होना और धार्मिक कक्षाओं को पढ़ाना किसी व्यक्ति की विद्वत क्षमता और ज्ञान का प्रामाण माना जाता है। ये भविष्य में नेता चुने जाने की आवश्यक शर्तो में से एक है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही नाम की घोषणा हुई, ईरान की सेना, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईंआरजीसी) और राजनीतिक नेताओं ने तुरन्त मोजतबा खामेनेई के प्राति निष्ठा की शपथ ली। आईंआरजीसी ने बयान जारी करते हुए कहा हम नए नेता आयतुल्लाह सैय्यद मोजतबा खामेनेई के हुक्म का पालन करने और खुद को वुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सेना के शीर्ष नेतृत्व ने भी अपनी पूरी वफादारी का वादा किया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई के सबसे शक्तिशाली पद संभालते ही ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों से हमला किया। मानों यह संकेत था कि अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत से भी उसकी रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया बल्कि यूं कहें कि ईरान अब और शक्ति से हमला करेगा। यह इससे साबित होता है कि अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में इस युद्ध में जबरदस्त नई मिसाइलों से हमला किया।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 29वां दीक्षांत समारोह और शिष्योपनयन संस्कार समारोह आयोजित किया

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित किया, आयुर्वेद की वैश्विक क्षमता और गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर बल दिया

(जीएनएस)।

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी) का 29वां दीक्षांत समारोह और शिष्योपनयन संस्कार समारोह आज वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के स्वतंत्रता भवन में आयोजित किया गया। इस समारोह में 'सर्टिफिकेट ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ' (सीआरएवी) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित विद्वानों की उपलब्धियों का उत्सव मनाया गया और आयुर्वेद की शाश्वत गुरु-शिष्य परंपरा को पुनः स्थापित किया गया।

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित किया।

इस अवसर पर श्री जाधव ने कहा कि काशी जैसे पवित्र शहर में विद्वानों की ऐसी गरिमामयी सभा को संबोधित करना अत्यंत गर्व का विषय है; उन्होंने कहा कि काशी आयुर्वेद ज्ञान का प्राचीन केंद्र है और वह भूमि है जिसका संबंध धन्वंतरि दिवोदास से है। धन्वंतरि दिवोदास को अष्टांग आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी

दूरदृष्टि ने बीएचयू को आयुर्वेद शिक्षा के ऐतिहासिक केंद्रों में से एक बनाया।

मंत्री महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा की प्रणाली मात्र नहीं है, बल्कि यह समग्र ज्ञान प्रणाली है जो स्वास्थ्य और जीवन के संबंध में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उन्होंने गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर बल दिया, जिसने पीढ़ी-दर-पीढ़ी आयुर्वेद के ज्ञान को संरक्षित और हस्तांतरित किया है। उन्होंने कहा कि धन्वंतरि, चरक, सुश्रुत और वाग्भट जैसे महान व्यक्तित्व इसी परंपरा से ही उभरे हैं।

श्री जाधव ने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के प्रयासों की सराहना की, जिसने सीआरएवी और एमआरएवी जैसे व्यवस्थित कार्यक्रमों के माध्यम से युवा चिकित्सकों को प्रख्यात और अनुभवी वैद्यों से सीधे सीखने का अवसर देकर इस परंपरा को बनाए रखा है। उन्होंने आयुर्वेद शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए आरएवी की शासी निकाय के अध्यक्ष और पद्म भूषण से सम्मानित वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, तथा आरएवी की निदेशक डॉ. वंदना सिरोहा के नेतृत्व की भी प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष प्रणालियों की बढ़ती पहुंच पर बल देते हुए, मंत्री ने कहा कि योग और आयुष को वैश्विक पहचान मिली है और वे भारत की स्वास्थ्य कूटनीति में लगातार योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा की मान्यता प्राप्त पद्धतियों—आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी—में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्वानों को संबोधित करते हुए, श्री जाधव ने कहा कि यह दीक्षांत समारोह न केवल शैक्षणिक उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि नई जिम्मेदारी की शुरूआत भी है। उन्होंने उनसे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ एकीकृत करने और आयुर्वेद को साक्ष्य-आधारित तथा विश्व स्तर पर स्वीकार्य बनाने में योगदान देने का आग्रह किया।

मेडट्रॉनिक और वैस्कुलर क्लिनिक लखनऊ ने उन्नत वैरिकोज वेन उपचार की पहुँच बेहतर बनाने के लिए की साझेदारी

लखनऊ, 11 मार्च 2026 झ लखनऊ स्थित वैस्कुलर क्लिनिक ने नसों से संबंधित रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए विशेष उपचार सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से मेडट्रॉनिक के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य मरीजों को समय पर जाँच, आधुनिक उपचार विकल्प और उनके घर के नजदीक समग्र देखभाल उपलब्ध कराना है। चिकित्सकीय विशेषज्ञता और उन्नत चिकित्सा तकनीक को साथ लाकर यह साझेदारी निदान और स्वस्थ होने की प्रक्रिया के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करती है। इसमें विशेष रूप से न्यूनतम आक्रामक उपचारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे मरीजों को कम दर्द हो, रिकवरी का समय घटे और वे जल्द ही अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौट सकें।

'हम पिछले एक दशक से अधिक समय से इस समुदाय की सेवा कर रहे हैं और हमने स्वयं देखा है कि समय के साथ मरीजों की जरूरतें कैसे बदली हैं,' वैस्कुलर क्लिनिक के कंसल्टेंट वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर सर्जन डॉ. यशपाल सिंह ने कहा। उन्होंने बताया कि वैरिकोज वेन का उपचार अब काफी विकसित हो चुका है और कई मामलों में अब इसके लिए बड़े ऑपरेशन या लंबी रिकवरी की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि वर्षों के चिकित्सकीय अनुभव को न्यूनतम आक्रामक उपचार विधियों के साथ जोड़कर उनका उद्देश्य नसों से संबंधित रोगों का अधिक प्रभावी उपचार करना और मरीजों को तेजी से स्वस्थ होने में मदद

करना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सहयोग के माध्यम से वे क्षेत्र के मरीजों के लिए विशेष नस उपचार सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना चाहते हैं और उन्हें जल्द से जल्द सामान्य दैनिक जीवन में लौटने में सहायता करना चाहते हैं।

जबकि वैरिकोज वेन्स और डीप वेन थ्रॉम्बोसिस (डीवीटी) जैसी नसों से संबंधित बीमारियाँ व्यापक रूप से पाई जाती हैं, इन्हें अक्सर केवल सौंदर्य से जुड़ी समस्या समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जब तक कि दर्दनाक जटिलताएँ सामने न आ जाएँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के संदर्भित आँकड़ों के अनुसार, दुनिया की लगभग 10झ 20% आबादी वैरिकोज वेन्स से प्रभावित है। लाखों लोग क्रॉनिक वेनस इंसफिशिएंसी के साथ जीवन जी रहे हैं, जिसमें दर्द, सूजन, त्वचा में परिवर्तन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और उन्नत मामलों में वेनस अल्सर भी हो सकता है। यह स्थिति इस बात को स्पष्ट रूप से दशार्ती है कि जल्दी निदान, समय पर उपचार और विशेषीकृत नस उपचार सेवाओं तक बेहतर पहुँच अत्यंत आवश्यक है।

नसों से संबंधित विकारों के लिए समर्पित केंद्र के रूप में स्थापित यह क्लिनिक परामर्श, जाँच सेवाएँ और उपचार विकल्पों को एक समन्वित देखभाल प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराता है, जिससे मरीजों के उपचार की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाया जा सके। उपचार के अलावा, यह क्लिनिक मरीजों को जागरूक करने, जीवनशैली संबंधी मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने पर भी ध्यान देता है, ताकि मरीजों को दीर्घकालिक नस स्वास्थ्य प्रबंधन में सहायता मिल सके।

हालाँकि नसों से संबंधित विकारों को अक्सर केवल एक सौंदर्य संबंधी समस्या समझ लिया जाता है, लेकिन यदि उनका उपचार न किया जाए तो वे मरीज के समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। एडहेसिव थेरेपी और रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन जैसे न्यूनतम आक्रामक उपचार विकल्पों को उन्नत तकनीकों के साथ एकीकृत करके यह क्लिनिक मरीजों को संपूर्ण देखभाल सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें निदान, उपचार और रिकवरी तक पूरी उपचार प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन मिलता है। यह सुव्यवस्थित दृष्टिकोण मरीजों को दीर्घकालिक राहत प्रदान करने के साथ-साथ उनके शारीरिक आराम और कार्यात्मक स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने में भी सहायता करने के लिए तैयार किया गया है।

'मेडट्रॉनिक में हम यह भली-भाँति समझते हैं कि हम अकेले सभी स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकते। वैस्कुलर वेन क्लिनिक के साथ मिलकर हम अग्रणी तकनीक और चिकित्सकीय विशेषज्ञता को एक साथ ला रहे हैं, ताकि उपचार तक पहुँच का विस्तार किया जा सके और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। यह सहयोग हमारे साझा मिशन—दर्द को कम करना, स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करना और जीवन को लंबा करना—को दशार्ता है,' मेडट्रॉनिक इंडिया में न्यूरोसाइंस और स्पेशियल्टी थेरेपीज के सीनियर डायरेक्टर प्रतीक तिवारी ने कहा।

टूसोल ने लॉन्च किया टूहर्ब्स की रेंज

टूसोल, बैद्यनाथ आयुर्वेद परिवार का एक आधुनिक मॉडर्न वेलनेस और पर्सनल केयर ब्रांड, ने आज 'टूहर्ब्स' रेंज के लॉन्च की घोषणा की। यह टूसोल वेलनेस प्लेटफॉर्म के तहत पारंपरिक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों की एक बेहद सोच-समझकर तैयार की गई और परिष्कृत पेशकश है। आज के स्वास्थ्य के प्रति जागरुक उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन की गई इस रेंज में चार एकल-जड़ी-बूटी फॉर्मूलेशन शामिल हैं— अश्वगंधा, गोक्षुर, ब्राह्मी और हड़जोड़। इन्हें साफ-सुथरे और आधुनिक स्वरूप में पेश किया गया है, जो क्लासिक आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक जीवनशैली की जरूरतों के बीच संतुलन बनाते हैं।

टूहर्ब्स रेंज को सावधानीपूर्वक चुनी गई जड़ी-बूटियों से विकसित किया गया है, जिन्हें उनके प्राकृतिक गुणों को संरक्षित रखने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में प्रोसेस किया जाता है। फॉर्मूलेशन की आवश्यकताओं के अनुसार, इन उत्पादों में सांद्रित और मानकीकृत अर्क शामिल हैं ताकि पौधे की प्राकृतिक विशेषताओं को बनाए रखते हुए उनके सक्रिय तत्वों में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक बैच की शुद्धता, सुरक्षा और अवयवों की अखंडता के लिए कड़ी गुणवत्ता जांच की जाती है, और इनका निर्माण ऐसी सुविधाओं में किया जाता है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस (जीएमपी) का पालन करती हैं और एफएसएसएआई आवश्यकताओं सहित सभी लागू नियामक दिशानिदेर्शों के अनुरूप हैं।

टूहर्ब्स रेंज की प्रत्येक जड़ी-बूटियों को आयुर्वेदिक साहित्य में उनके विशिष्ट स्वास्थ्य लाभों के लिए पारंपरिक रूप से महत्व दिया गया है, जैसे तनाव संतुलन, सहनशक्ति और समग्र जीवन शक्ति के लिए अश्वगंधा, शक्ति, एंड्योरेंस और सक्रिय जीवनशैली के सहयोग के लिए गोक्षुर, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता के लिए ब्राह्मी, और हड्डियों तथा जोड़ों की मजबूती के लिए हड़जोड़।

मुख्य रूप से निवारक और लाइफस्टाइल संबंधित वेलनेस के लिए तैयार की गई टूहर्ब्स रेंज को किसी विशेष बीमारी के उपचार के बजाय संतुलित जीवनशैली के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया है। यह विशेष रूप से व्यस्त दिनचर्या वाले कामकाजी पेशेवरों, प्लांट-बेस्ड ताकत की तलाश करने वाले फिटनेस उत्साही लोगों, एकाग्रता और स्पष्टता को प्राथमिकता देने वाले छात्रों एवं बौद्धिक श्रम करने वालों और निवारक वेलनेस रूटीन में पारंपरिक जड़ी-बूटियों को शामिल करने के इच्छुक वयस्कों के लिए उपयुक्त है।

लॉन्च के दौरान बोलते हुए टूसोल के सह-संस्थापक अधिराज शर्मा ने कहाः "पीढ़ियों से अश्वगंधा, ब्राह्मी, गोक्षुर और हड़जोड़ जैसी जड़ी-बूटियाँ भारतीय घरों में रोजमर्रा के स्वास्थ्य का हिस्सा थीं। हालाँकि, समय के साथ जैसे-जैसे जीवनशैली तेज और अधिक शहरी होती गई, वह मेल-जोल धीरे-धीरे कम होता गया। सुविधा ने परंपरा की जगह ले ली और कहीं न कहीं हमने इनका उपयोग करना बंद कर दिया। टूहर्ब्स के साथ हम इन सदियों पुरानी जड़ी-बूटियों को वापस रोजमर्रा की जिंदगी में लाना चाहते थे - न केवल पुरानी यादों के कारण, बल्कि लोगों को प्राकृतिक वेलनेस से इस तरह से फिर से जुड़ने में मदद करने के लिए जो सहज, प्रामाणिक, सुलभ और एक स्वस्थ, अधिक संतुलित जीवनशैली के अनुरूप महसूस हो।"

इसी विजन को दोहराते हुए, टूसोल के सह-संस्थापक ऋषि राज शर्मा ने कहाः "हम एक ऐसी विरासत से आते हैं जो जड़ी-बूटियों को केवल सामग्री के रूप में नहीं, बल्कि दैनिक स्वास्थ्य के एक अभिन्न अंग के रूप में देखती है। साथ ही, हम यह भी समझते हैं कि आज के उपभोक्ता जागरूक हैं और शुद्धता, पारदर्शिता व निरंतरता की अपेक्षा रखते हैं।

उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 332वीं रिपोर्ट पर प्रेस विज्ञप्ति

(जीएनएस)।

श्री तिरुची शिवा की अध्यक्षता में राज्य सभा की विभाग-संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारी उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों (2026-27) पर अपना तीन सौ बत्तीसवां (332वां) प्रतिवेदन 11 मार्च, 2026 को संसद में प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में ऑटोमोटिव उद्योग, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों से संबंधित मंत्रालय के बजटीय आवंटन और प्रमुख योजनाओं को कवर किया गया है।

समिति ने राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 272 के तहत भारी उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों 2026-27 (मांग सं. 48) की जांच की । समिति ने मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ-साथ और इसके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और संगठनों के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिए। प्रतिवेदन में शामिल समिति की प्रमुख सिफारिशें संक्षेप में निम्नानुसार हैं।

बजटीय आवंटनः यथार्थवादी बजटिंग और संतुलित व्यय की आवश्यकता

समिति ने नोट किया कि मंत्रालय के लिए बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.) 2026-27, 7,939.90 करोड़ रुपये हैं, जबकि मंत्रालय द्वारा अनुमानित आवश्यकता 9,484.32 करोड़ रुपये की है, जो लगभग 16 प्रतिशत की बड़ी कमी दशार्ता है। राजस्व व्यय कुल परिव्यय का 99.96 प्रतिशत (7,937.08 करोड़ रुपये) है, जबकि पूंजीगत व्यय को बजट प्राक्कलन 2025-26 में 502 करोड़ रुपये से घटाकर नगण्य 2.82 करोड़ रुपये (0.04 प्रतिशत) कर दिया गया है, जो बहुत कम है।

समिति ने बजट प्राक्कलन को संशोधित प्राक्कलन स्तर पर बार-बार घटाए जाने पर चिंता जताई है — 2024-25 और 2025-26 में संशोधित प्राक्कलन स्तर पर आवंटन को लगभग एक-तिहाई कम कर दिया गया था — जो व्यय नियोजन में अधिआकलन और प्रणालीगत कमजोरियों की ओर इशारा करता है। संशोधित प्राक्कलन के उपयोग में गिरावट की प्रवृत्ति — जो 2022-23 में 84.23 प्रतिशत, 2023-24 में 76.87 प्रतिशत, और 2024-25 में 58.90 प्रतिशत थी — को भी चिंता का विषय बताया गया।

समिति की प्रमुख सिफारिशेंः

मंत्रालय को मध्यम अवधि में राजस्व और पूंजीगत परिव्यय के बीच अधिक संतुलित समन्वय फिर से स्थापित करना चाहिए और टिकाऊ औद्योगिक आस्तियों, परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना के आधुनिकीकरण, और दबाव में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की समय-बद्ध रूप से पुनर्संरचना के लिए पूंजी का आवंटन बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

जिन स्कीमों में पूंजी का लंबे समय से अल्प उपयोग हो रहा है, उनके लिए स्कीम विशेष आधारित खर्च कम करने की योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें मंजूरी की फ्रंट लोडिंग और लक्ष्यों को यथार्थवादी रूप से तय करना शामिल हो।

मंत्रालय को अपनी आंतरिक संसाधन-आकलन प्रणाली को मजबूत करना चाहिए और वित्त मंत्रालय के साथ शीघ्र और डेटा-आधारित परामर्श करना चाहिए ताकि अत्यावश्यक बहु-वर्षीय योजनाओं को पूवार्नुमेय और पर्याप्त धनराशि मिल सके।

पीएम ई ड्राइवः इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में सेगमेंट संबंधी असंतुलन को ठीक करना

पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना , जिसकी कुल लागत 10,900 करोड़ रुपये है (अप्रैल 2024 से मार्च 2028 तक प्रभावी), को बजट प्राक्कलन 2026-27 में 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 31 जनवरी 2026 की स्थिति तक, कुल 16,56,335 इलेक्ट्रिक गाड़ियों (ईवी) को 28,26,634 ईवी के संशोधित लक्ष्य के अनुसार प्रोत्साहन दिया गया है — यह लगभग 58.6 प्रतिशत की उपलब्धि है।

प्रगति इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (ई-2डब्ल्यूः 14,31,133 यूनिट्स) और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर एल 5 (ई-3 डब्ल्यू एल5: 2,21,600 यूनिट्स) सेगमेंट में ही अधिकाधिक रूप से संकेन्द्रित है। इसके विपरीत,इलेक्ट्रिक ट्रक (ई-ट्रक) और इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) के क्षेत्र में कोई उपलब्धि दर्ज नहीं की गयी है, और इलेक्ट्रिक रिक्शा/इलेक्ट्रिक कार्ट (ई-रिक्शा/ई-कार्ट) सेगमेंट सिर्फ. 3,602 यूनिट्स तक ही पहुँच पाया है, जबकि संशोधित लक्ष्य 39,034 का था। इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस (ई- एम्बुलेंस) के मामले में भी प्रगति शून्य पर टिकी हुई है।

समिति की मुख्य सिफारिशेंः

ध ई-2डब्ल्यू के लिए मांग संबंधी प्रोत्साहन को एक व्यवस्थित टेपरिंग मैकेनिज्म के साथ 31 मार्च 2028 तक बढ़ाएं, जो पीएम ई ड्राइव का आखिरी साल है, ताकि उस सेगमेंट में नीतिगत झटके से बचा जा सके जिसने मजबूती से बदलावों को अपनाया है और जो बड़े पैमाने पर आजीविका संबंधी समर्थन प्रदान करता है।

ध 1,10,596 ई-रिक्शा/ई-कार्ट के मूल लक्ष्य को पुनः बहाल करें, प्रोत्साहनों को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाएं, और नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली गाड़ियों के अप्राधिकृत उत्पादन और प्रचालन को रोकने के लिए राज्यों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके प्रवर्तन संबंधी उपाय करें। समिति ने नोट किया कि लगभग 4.75 लाख बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा बिना प्रमाणीकरण, रजिस्ट्रेशन या बीमा के चल रहे हैं।

ध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और बड़े शहरों में डीजल थ्री-व्हीलर के लगातार प्रचलन को देखते हुए, ई-3डब्ल्यू एल5 के लिए एक संशोधित और परिवर्धित लक्ष्य तय करें और 31 मार्च 2028 तक प्रोत्साहनों को जारी रखें।

ध ई-ट्रक और ई-एम्बुलेंस के लिए दिशानिर्देश, मॉडल संबंधी मंजूरी और विनिर्माणकताओं की ऑनबोर्डिंग को अंतिम रूप देने के लिए एक सुनियोजित निगरानी तंत्र तथा विस्तृत कार्य योजना के साथ स्पष्ट और बिना किसी समझौते वाली समय-सीमा तय करें ।

ध निविदा को अंतिम रूप देने के बाद ई-बसों को काम पर लगाने के लिए कार्यान्वयन संबंधी समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ एक मजबूत निगरानी अवसंरचना स्थापित करें।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चरः निजी भागीदारी का विस्तार करना

समिति ने नोट किया कि पीएम ई-ड्राइव के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन घटक के लिए तैयारी संबंधी कदम झ जिसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर नियुक्त करना और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा बेंचमार्क व्यय का संशोधन शामिल है झ पूरे हो चुके हैं। हालांकि, निधियों का उपयोग अभी भी सीमित है।

समिति ने समुक्ति की कि मौजूदा अलग-अलग राजसहायता संरचना श्रेणी 'ग' (सरकारी/पीएसयू से जुड़ी श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी स्थल) और 'घ' (बैटरी स्वैपिंग और बैटरी चार्जिंग स्टेशन) में चार्जर के लिए सीमित सहायता प्रदान करती है, जिससे निजी निवेश पर रोक लग सकती है और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और अधिक मांग वाले स्थलों पर चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार धीमा हो सकता है।

समिति की प्रमुख सिफारिशेंः

श्रेणी 'ग' और 'घ' में चार्जर के लिए व्यवस्थित समर्थन प्रदान करने के लिए राजसहायता की संरचना की

कूलिंग के भविष्य का आगाज। डायकिन इंडिया ने पेश की एआई-पावर्ड VRV अल्फा और 2026 की अत्याधुनिक एसी रेंज

लखनऊ, 11 मार्च 2026: जापानी तकनीक और भारतीय विश्वास के संगम, डायकिन एयरकंडीशनिंग इंडिया ने आज लखनऊ में अपने बहुप्रतीक्षित 2026 प्रोडक्ट लाइनअप का अनावरण कर कूलिंग जगत में एक नई कांति की शुरूआत की। ऊर्जा दक्षता और स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल' के संकल्प के साथ, डायकिन ने अपनी नई इएए 2026 स्टार रेटेड रूम एसी रेंज और एआई-संचालित VRV अल्फा सीरीज की बाजार में उतारा है। राष्ट्रीय सम्मानः डापकिन को भारत सरकार द्वारा 'नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025' से नवाजा गया है। मॉडल FTM50 को 'एएलायंस ऑफ द ईयर चुना गया, जिसे राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू की की उपस्थिति में प्रदान किया गया। 54ºC की गर्मी भी अब लगेगी सुहानीः रूम एसी का नया अवतार डायकिन की 2026 रूम एसी रेंज को "रिस्पॉन्सिबल कूलिंग के दर्शन पर तैयार किया गया है। यह सिर्फ एक एसी नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है.

स्ट्रीमर डिस्चार्ज और स्विंग कंप्रेसरः शुद्ध हवा और अधिकतम बिजली बचत का बेजोड़ संगम।

भीषण गर्मी का समाधानः हाई-एम्बिएंट परफॉरमेंस तकनीक, जो 54ºC के प्रचंड तापमान में भी शिमला जैसी ठंडक दे।

स्मार्ट फीचरसः 101' कनेक्टिविटी और अल्ट्रा-क्काइट (बेहद शांत) ऑपरेशन के साथ प्रीमियम घरों की पहली पसंद। VRV अल्फाः जब कूलिंग को मिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दिमाग बड़े प्रोजेक्ट्स और आलीशान घरों के लिए डायकिन ने श्फ्र अल्फा पेश किया है। यह दुनिया का ऐसा सिस्टम है जो अक के जरिए खुद फैसले लेता है, मौसम के बदलाव को भांपता है और कम से कम बिजली में सबसे सटीक कूलिंग देता है। यह 21वीं सदी के स्मार्ट इंडिया की पहचान है। नेतृत्व का विजनः "जापानी विरासत, भारतीय जरूरत" इस मील के पत्थर पर श्री कंवलजीत जावा (चेयरमैन एवं एमडी, डायकिन इंडिया) ने श्री रवि तनेजा (मार्केटिंग हेड, नॉर्थ इंडिया) और श्री शक्ति सिंह (ब्रांच ऑपरेशंस हेड, ईस्ट यूपी) की उपस्थिति में कहाः "हमारा 60+ मॉडलों का नया 2026 लाइनअप हमारी जापानी नवाचार की विरासत और भारतीय जरूरतों का एक सुंदर मेल है। तीन फैक्ट्रियों की ताकत के साथ, हम न केवल क्षमता बढ़ा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल समाधान भी प्रदान कर रहे हैं।" मूल्य संशोधन की जानकारी डायकिन ने यह भी सूचित किया है कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण, अप्रैल 2026 से उत्पादों की कीमतों में 7% से 12% तक की वृद्धि प्रभावी होगी। डायकिन इंडिया के बारे में: डायकिन एयरकंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (DAIPL), जापान की डायकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी भारत में अत्याधुनिक और ऊर्जा-कुशल एयर कंडीशनिंग समाधानों के लिए अग्रणी नाम है।

ड्यूटी से गायब मिले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई निलंबितः एस पी

(जीएनएस)।

हरदोई/ बेनीगंज पुलिसकर्मियों की लापरवाही को लेकर पुलिस अधीक्षक ने अपनाया कड़ा रूख ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाए जाने और एक सड़क दुर्घटना के मामले में समय पर कार्रवाई न करने के आरोप में दो पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई में तैनात उपनिरीक्षक पन्ना लाल सोनी की ड्यूटी कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पंचास्थानीय चुनाव कार्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगाई गई थी। यह ड्यूटी अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि यहां चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री सुरक्षित रखी जाती है। जांच के दौरान जब अधिकारियों ने ड्यूटी का निरीक्षण किया तो उपनिरीक्षक पन्ना लाल सोनी मौके पर मौजूद नहीं मिले। इसे ड्यूटी के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए पुलिस अधीक्षक ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिए।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नेटवर्क समस्या का समाधान, लग्गा-बग्गा में लगेंगे बीएसएनएल के दो नए टावर

(जीएनएस)।

पीलीभीत। जनपद के सीमावर्ती और वन क्षेत्र से घिरे इलाके में लंबे समय से चली आ रही मोबाइल नेटवर्क समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नेपाल सीमा से सटे कलीनगर क्षेत्र के लग्गा-बग्गा गांव में बीएसएनएल के दो नए मोबाइल टावर लगाने के प्रस्ताव को वन विभाग से मंजूरी मिल गई है। इस पहल को केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों का परिणाम बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नेपाल सीमा के निकट होने और घने वन क्षेत्र के कारण मोबाइल नेटवर्क की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। इसके चलते स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ वन विभाग के अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को भी संचार व्यवस्था में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय स्तर पर प्रयास किए। उनके प्रयासों के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 10 मार्च 2026 को आवश्यक वन स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके बाद दूरसंचार मंत्रालय के निर्देश पर जल्द ही मोबाइल टावरों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

इन टावरों के लगने से पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आसपास रहने वाले हजारों ग्रामीणों को बेहतर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी। साथ ही सीमा क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों और वन विभाग के कर्मचारियों को भी संचार व्यवस्था मजबूत होने से अपने कार्यों में काफी सहूलियत मिलेगी।

स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सीमावर्ती और वन क्षेत्र में मजबूत संचार व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। टावरों की स्थापना से न केवल नेटवर्क समस्या का समाधान होगा, बल्कि क्षेत्र के विकास, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा

डीपीआईआईटी ने कूलिंग और स्मार्ट उपकरण प्रौद्योगिकियों में उद्योग-स्टार्ट-अप सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वोल्टास लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कूलिंग और स्मार्ट उपकरण तंत्र में उद्योग-स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देने के लिए टाटा एंटरप्राइज की वोल्टास लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस सहयोग का मकसद हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी), उन्नत नियंत्रण प्रणाली, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग आधारित निदान, आईओटी-सक्षम स्मार्ट उपकरण और विनिर्माण एवं सेवा संचालन में डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे स्टार्टअप्स को शामिल करना है।

इस पहल के तहत, डीपीआईआईटी और वोल्टास लिमिटेड के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया पहल, भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के तहत नवाचार चुनौतियों का आयोजन करने और उद्योग जगतसे जुड़ी समस्याओं पर केंद्रित हैकथॉन आयोजित करने पर विचार करेगी।

इस अवसर पर डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव श्री संजीव ने कहा कि यह सहयोग सरकार के उन प्रयासों

के अनुरूप है, जिनका मकसद उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच, विशेष रूप से उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में, अधिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की साझेदारियाँ स्टार्टअप्स को उद्योग जगत की जरुरतों के मुताबिक समाधान विकसित करने और उनका परीक्षण करने के अवसर प्रदान कर सकती हैं।

इस साझेदारी के तहत, डीपीआईआईटी स्टार्टअप इंडिया पहल के जरिए वोल्टास लिमिटेड के साथ मिलकर, उद्योग जगत की उभरती जरुरतों के मुताबिक स्टार्टअप्स की पहचान करेगा। चयनित स्टार्टअप्स को उत्पाद विकास में सहयोग के लिए मेंटरशिप, तकनीकी मार्गदर्शन, परीक्षण अवसंरचना तक पहुँच और बाजार संपर्क के अवसर मिल सकते हैं।

ऊर्जा-कुशल शीतलन प्रणाली, वायु गुणवत्ता निगरानी और फिल्ट्रेशन तकनीकें, उन्नत इन्वर्टर नियंत्रण, पूवार्नुमानित रखरखाव समाधान, रेफ्रिजरेंट सुरक्षा प्रणाली और स्थापना तथा सर्विसिंग के लिए डिजिटल उपकरण जैसे क्षेत्र प्रमुख फोकस में हो सकते हैं।

चयनित स्टार्टअप, उत्पाद सत्यापन और प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिए वोल्टास इंजीनियरिंग टीमों के साथ संरचित प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (पीओसी) कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं। यह सहयोग वोल्टास के सेवा नेटवर्क के जरिए फील्ड परीक्षणों को भी सरल बना सकता है, जिससे समाधानों के परीक्षण और परिष्करण में मदद मिलेगी।

दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में डीपीआईआईटी के निदेशक डॉ. सुमीत कुमार जरंगल और वोल्टास लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री मुकुंदन मेनन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

रूप दुगार्पाल ओटीटी सीरीज 'संकल्प' से कर रही हैं डेब्यू, बताया प्रकाश झा के साथ काम करने का एक्सपीरिएंस

(जीएनएस)।

एक्ट्रेस रूप दुगार्पाल ने टीवी इंडस्ट्री में खूब काम किया है। कई यादगार सीरियल में उन्हें देखा गया है। अब वो अपना ओटीटी डेब्यू कर रही हैं। रूप प्रकाश झा की 'संकल्प' से वेब स्पेस में डेब्यू करने जा रही हैं। इस सीरीज में नाना पाटेकर, संजय कपूर, मोहम्मद जीशान अय्यूब, क्रांति प्रकाश झा और मेघना मलिक जैसे कुछ बेहतरीन नाम हैं।

सीरीज और अपने रोल के बारे में और बताते हुए रूप कहती हैं, "शानदार कास्ट एक अहम वजह है कि मैं शो में शामिल होने के लिए उत्साहित थी। जब सभी के पास शानदार काम होता है, तो आप जानते हैं कि सेट पर और सेट के बाहर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाना पाटेकर सर, प्रकाश सर के आस-पास रहना मुझे एक्टिंग, मेकिंग और यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी के अलग-अलग पहलुओं के बारे में सिखाने जैसा था। मेघना मलिक मैम से भी सीखने के लिए बहुत कुछ था, हम लंच और डिनर के दौरान भी बॉन्ड बनाते थे। वह बहुत शानदार एक्टर और बेहतरीन इंसान हैं।"

रूप इस सीरीज में माधुरी का किरदार निभा रही हैं - मोहम्मद जीशान अय्यूब की पत्नी। उनके बारे में और बताते हुए रूप कहती हैं, "जीशान एक शानदार को-एक्टर हैं, ठरऊ से आने और फिल्मों और वेब स्पेस में इतना काम करने के बाद, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ था। सीन्स के प्रति उनका नपा-तुला

नजरिया, भाषा पर उनकी पकड़ और जबरदस्त एनर्जी हमारे साथ के सीन्स के दौरान बहुत मददगार रही। मैं हर दिन सेट का इंतजार करती थी।"

दिलचस्प बात यह है कि रूप का डळळ पर डेब्यू उनके करियर में काफी देर से हुआ। इस बारे में वह कहती हैं, "मुझे लगता है कि 2019 तक, मैंने टीवी से आगे जाने के बारे में नहीं सोचा था, जब कोविड आया और हमारी ज़िंदगी बदल गई, लोगों को गुजरते देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी छोटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे एक्सपेरिमेंट करने और ऐसी चीजें करने का मन हुआ जिनसे मुझे डर लगता था।

थिएटर उनमें से एक था। बिना कट, बिना रीटेक, महीने भर की रिहर्सल का आइडिया मेरे लिए अजीब और डरावना भी था। लेकिन ज़िंदगी की अनिश्चितता के एहसास ने मुझे हिम्मत दी और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। मैंने थिएटर किया, स्टेज पर होना और बिना किसी परेशानी के यह एक बहुत ही संतोषजनक सफर था। इसने मुझे टीवी से आगे बढ़कर वेबस्पेस में जाने की हिम्मत दी। मुझे लगता है कि हर चीज अपने समय पर होती है और हर किसी का सफर अलग होता है। मेरा सफर ऐसे ही होना था, मैं बहुत खुश हूँ कि यह अपने आप हुआ। सालों की संख्या मायने नहीं रखती।"रूप बताती हैं कि प्रकाश झा की कक्षानी में, काम करना किसी इंस्टीट्यूशन में सीखने जैसा लगता था और फिर भी एक्टिंग के साथ मजा आता था और यादगार यादें बनती थीं।

गैस एजेंसी संचालकों के साथ पुलिस-प्रशासन की बैठक, वितरण व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश

स्टॉक व रिफिल की रोजाना जानकारी रखने और ओटीपी से ही सिलेंडर देने के निर्देश

(जीएनएस)।

पीलीभीत। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में गैस वितरण व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्राधिकारी नगर तथा जनपद की विभिन्न गैस एजेंसियों के स्वामी व प्रोपराइटर मौजूद रहे।

बैठक के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी ने गैस एजेंसी संचालकों को वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एजेंसी संचालक प्रतिदिन गैस सिलेंडरों के रिफिल और स्टॉक की अद्यतन जानकारी रखें तथा उपभोक्ताओं को नियमानुसार ओटीपी के माध्यम से ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएं।

जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए कि दो रिफिल सिलेंडरों की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतराल अनिवार्य रूप से रखा जाए और एजेंसी के सॉफ्टवेयर को भी इसी के अनुरूप अपडेट किया जाए, ताकि निर्धारित अवधि से पहले दोबारा बुकिंग संभव न हो सके।

अधिकारियों ने एजेंसी संचालकों से कहा कि वे स्वयं प्रतिदिन एजेंसी और गोदाम पर मौजूद रहकर स्टॉक व वितरण की निगरानी करें। साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग होटल, रेस्टोरेंट या अन्य व्यावसायिक संस्थानों में न होने दें और हॉकरों को भी कालाबाजारी, घटतौली या अवैध रिफिलिंग से दूर रहने के लिए सख्त निर्देश दें।

बैठक में यह भी कहा गया कि किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति बनने पर तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को सूचना दी जाए। पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गैस एजेंसियों के गोदामों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील भी की गई।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनपद में गैस की कोई कमी नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

बिंद्रा कोल्ड स्टोरेज मे आलू लेकर आये एक किसान की ट्राली के नीचे दबकर दर्दनाक मौत

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। जिला प्रशासन की लापरवाही एव कोल्ड स्टोरेज मालिकों की अव्यवस्थाओ के चलते मंगलवार की देर शाम बिंद्रा कोल्ड स्टोरेज मे आलू लेकर आये एक किसान की ट्राली के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गयी। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर फरार हो गया है। कोल्ड स्टोरेज मे आलू रखने आये किसानो ने स्टोर मालिक पर अव्यवस्था का आरोप लगाया है।

बताते चले कि मंगलवार की शाम करीब 4 बजे जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरौली निवासी 55 वर्षीय किसान उमेश चंद्र वर्मा पुत्र भगवती प्रसाद नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंद्रा कोल्ड स्टोरेज मे आलू रखने के लिए गये थे कोल्ड स्टोरेज में फैली अव्यवस्थाओं के कारण वहां आड़े तिरछे खड़े ट्रैक्टर ट्राली के बैक करने के दौरान किसान उमेशचंद्र वर्मा की ट्राली के नीचे आ जाने से दर्दनाक मौत हो गयी दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर बैक कर रहा चालक ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर फरार हो गया तथा कोल्ड स्टोरेज मे अफरातफरी मच गयी किसान को

आननफानन मे जिला अस्पताल पहुंचाया जहा चिकित्स्कों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सबसे बड़ी दुःख की यह बात रही कि कोल्ड स्टोरेज परिसर मे इतनी बड़ी घटना के बाद भी मृतक के परिजनों की कोई सुध नहीं ली। मेंथा किसान समिति के अध्यक्ष डा0 राजेश कुमार वर्मा ने घटना पर दुःख प्रकट करते हुए बताया कि इस हादसे से किसान का परिवार गहरे संकट में आ गया है। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है और घर में मातम का माहौल है। परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करा कर मृतक किसान के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए तथा कोल्ड स्टोरेज में फैली अव्यवस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।

नियमों की अनदेखी अव्यवस्थाओ का बोलबाला

किसानो का सुचारु रूप से कोल्ड स्टोरेज मे आलू रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा टोकन की व्यवस्था करने के बाद भी कोल्ड स्टोरो मे टोकन न दिये जाने से किसानो मे अफरातफरी का महौल है जिससे किसानो मे होड़ मची हुई है कोल्ड स्टोरेज मालिक गेट पर गेटमैन तक की व्यवस्था नहीं किये हुए है जिससे कोल्ड स्टोरेज मे आड़ी तिरछी ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हुई है उल्लेखनीय हो कि कोल्ड स्टोरेज मालिको ने किराया बढ़ाने को लेकर सभी लामबंद हो गये थे लेकिन व्यवस्था के नाम पर कोई भी कोल्ड स्टोर मालिक रुचि नहीं ले रहा हैं ।

परिवार पर टूटा दुःखो का पहाड

मृतक किसान उमेशचंद्र के एक मात्र पुत्र रवि था जिसकी 4 वर्ष पूर्व नयागाँव के निकट दुर्घटना मे मौत हो गयी थी मृतक उमेशचंद्र के ऊपर एक पुत्री व दो पौत्रियों की शादी की जिम्मेदारी है घर के कमाऊ व्यक्ति की मौत से गाँव मे कोहराम मचा हुआ है।

बिहार के किसानों की 13 मार्च को लगेगी लॉटरी, अकाउंट में आएंगे 50% अधिक पैसे?

(जीएनएस)।

देशभर के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से जिस किस्त का इंतजार किया जा रहा था, अब वह जल्द ही किसानों के बैंक खातों में पहुंचने वाली है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

इस बार भी पात्र किसानों के खातों में 2000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों के दस्तावेजों में कोई कमी होगी या जिनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा, उन्हें यह किस्त नहीं मिलेगी। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते पोर्टल पर अपना स्टेटस जांच लें और ाङउ जैसी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किस्त आने में कोई दिक्कत न हो।

कब जारी होगी पीएम किसान की 22वीं किस्त?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक

खातों में 2000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। योजना की शुरूआत से अब तक सरकार 21 किस्तें किसानों को दे चुकी है और अगली किस्त का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था।

पीएम किसान की 22वीं किस्त के लिए ाङउ पूरा करना जरूरी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए ाङउ अनिवार्य है। किसान डळढ के जरिए पीएम किसान पोर्टल पर ाङउ पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जिन किसानों को बायोमेट्रिक के जरिए ाङउ कराना है, वे अपने नजदीकी उरउ सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर ाङउ नहीं कराया गया तो किस्त खाते में आने में परेशानी हो सकती है।

ढट ङ्रल्ल ङ्ल्लः साल में मिलते हैं 6000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत साल 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

खेती के काम में मिलती है मदद

इस योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को आर्थिक सहारा देना है। किस्त के रूप में मिलने वाली राशि से किसान बीज, खाद और खेती से जुड़ी दूसरी जरूरी चीजों का खर्च आसानी से उठा पाते हैं। इससे किसानों को खेती के सीजन में आर्थिक राहत मिलती है।

बिहार के किसानों को मिल सकता है एक और फायदा

बिहार के किसानों के लिए एक और राहत की संभावना है। राज्य सरकार की कपूर्री ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है। ऐसे में कई किसानों को केंद्र की पीएम किसान योजना के साथ-साथ राज्य सरकार की इस योजना का भी लाभ मिल सकता है। ऐसा होता है तो बिहार के किसानों के खाते में 2000 की जगह 3000 रुपये भेजे जाएंगे।

48000000 की प्राइज मनी से भरा पाकिस्तान का कटोरा, टी20 विश्व कप हारने पर भी मिले कई टीमों से ज्यादा पैसे

(जीएनएस)।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शोर थम चुका है, अब बारी धन राशि के हिसाब की है। मैदान पर तिरंगा लहराने वाली टीम इंडिया ने सिर्फ वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी ही नहीं जीती, बल्कि प्राइज मनी के मामले में भी झंडे गाड़ दिए। आईसीसी (कउउ) ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि किस टीम के खाते में कितने करोड़ रुपये आए हैं। इस बीच पाकिस्तान को भी एक बड़ी रकम मिली है, जो चौंकाने वाली है।

वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद रोहित एंड कंपनी पर पैसों की जबरदस्त बारिश हुई है। आईसीसी की रिलीज के मुताबिक भारतीय टीम को लगभग 24.25 करोड़ रुपये का इनाम मिला है। यह रकम टीम की जीत, मैच बोनस और फाइनल तक के अजेय सफर को जोड़कर तय की गई है।

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का

क्या रहा हाल?

फाइनल की हार के बावजूद कीवी टीम यानी न्यूजीलैंड के खाते में 13.08 करोड़ रुपये आए हैं। वहीं, सेमीफाइनल की रेस में पिछड़ने वाली दक्षिण अफ्रीका को 9.24 करोड़ और इंग्लैंड को 8.96 करोड़ रुपये मिले हैं।

बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो उनके हाथ महज 4.80 करोड़ रुपये ही लगे हैं। आईसीसी ने साफ किया है कि हर टीम को मिलने वाली लगभग 2 करोड़ रुपये की पार्टिसिपेशन फीस भी इस फाइनल लिस्ट में शामिल है।

कैसे बांटा गया अमाउंट

आईसीसी ने कुल 103 करोड़ रुपये का एक पूल बनाया था। इस पैसे को बांटने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। इसमें सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि आप टूनार्मेंट के किस पड़ाव तक पहुंचे हैं, उसका भी रिवॉर्ड मिलता है। हर टीम को मिलने वाली बेस फीस के साथ-साथ मैच जीतने पर मिलने वाले बोनस को जोड़कर यह फाइनल अमाउंट तैयार किया गया है।

किसकी झोली में कितने करोड़?

विजेता (भारत): 24.25 करोड़

उप-विजेता (न्यूजीलैंड): 13.08 करोड़

दक्षिण अफ्रीकाः 9.24 करोड़

इंग्लैंडः 8.96 करोड़

पाकिस्तानः 4.80 करोड़

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय सुरक्षा, मानकीकरण और प्रवासन मार्गों पर केंद्रित 'क्वांटम सुरक्षित संचार' पर कार्यशाला का आयोजन किया

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में "क्वांटम सुरक्षित संचार" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों, वैज्ञानिक निकायों, मानकीकरण संगठनों, उद्योग संघों और उभरती क्वांटम प्रौद्योगिकी कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में क्वांटम युग में दूरसंचार नेटवर्क की मजबूती बढ़ाने के लिए नीतिगत, सुरक्षा और परिचालन सम्बंधी दृष्टिकोणों पर विचार-विमर्श किया।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों, क्वांटम-पश्चात क्रिप्टोग्राफिक संक्रमण रणनीतियों, वैश्विक मानकीकरण पहलों और क्वांटम-सुरक्षित संचार नेटवर्क की ओर प्रवास के लिए आवश्यक इको सिस्टम समन्वय पर संरचित विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। चचाओं में दूरसंचार अवसंरचना में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक क्रिप्टोग्राफिक प्रणालियों के दीर्घकालिक जोखिमों से निपटने के लिए प्रारंभिक और समन्वित भागीदारी के महत्व पर बल दिया गया।

सत्र का शुभारंभ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सलाहकार (बीबी एंड पीए) डॉ. अब्दुल कयूम के उद्घाटन भाषण और स्वागत भाषण से हुआ। इसके बाद ट्राई के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने उद्घाटन भाषण दिया।